ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-6* July- 2021
Innovation The Research Concept

राजनीतिक दल और महिलाएँ छत्तीसगढ़ के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में (1950-2000)

Political Parties and Women With reference to the Parliamentary and Legislative Assembly elections of Chhattisgarh (1950-2000)

Paper Submission: 05/07/2021, Date of Acceptance: 15/07/2021, Date of Publication: 25/07/2021

आभा आर. पाल
प्रोफेसर एवं हेड,
इतिहास विभाग,
रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

अनामिका शर्मा
गेस्ट फैकल्टी
इतिहास विभाग,
रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छत्तीसगढ, भारत

सारांश

राजनीतिक दल देश की संसदीय शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जनमत को संगठित करते हैं। चुनावों का आयोजन करते हैं। राजनीतिक प्रश्नों पर जनता को शिक्षित करते हैं। जनता के दायित्वों का प्रचार करते हैं और सरकार तथा जनसामान्य के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। भारत में अनेक दल है इनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं जिनका प्रभाव समूचे देश अथवा कई राज्यों में है और कुछ राज्य स्तर के हैं जिनका प्रभाव केवल राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। चुनाव आयोग ने प्रथम आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के 14 तथा राज्य स्तर के 51 दलों को मान्यता प्रदान की थी।1

राजनीतिक दल किसी भी देश की रजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन में तेल का कार्य करते हैं, इसलिए दलीय व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग समझा जाता है। छत्तीसगढ़ में 1950 से 2000 के मध्य होने वाले संसदीय निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन में महिलाओं को चुनाव में विभिन्न दलों के माध्यम से मैदान में उतारा गया है जिसका विश्लेषण शोध पत्र में करने का प्रयास किया गया है और यह समझने की कोशिश की गयी है कि महिलाओं को विभिन्न राजनीतिक दलों में पुरूषों के मुकाबले कितनी संसदीय और विधानसभा सीटें प्रदान की है जिनसे राजनीति में उनके योगदान का मुल्यांकन किया जा सके।

Political parties play an important role in the parliamentary form of government in the country. They organize public opinion. organize elections. Educate the public on political questions. Promote the responsibilities of the people and act as a link between the government and the general public. There are many parties in India, some of them are at the national level, whose influence is in the whole country or in many states and some are at the state level, whose influence is limited to only a particular state or region. In the first general election, the Election Commission had given recognition to 14 national level and 51 state level parties.1

Political parties act as oil in the political system of any country, so the party system is considered an integral part of the political system. In the parliamentary elections and assembly elections held between 1950 and 2000 in Chhattisgarh, women have been fielded through various parties in the elections, which has been analyzed in the research paper and an attempt has been made to understand that women How many parliamentary and assembly seats have been provided to men in different political parties, so that their contribution to politics can be assessed.

मुख्य शब्द : राजनीति, महिला, छत्तीसगढ़, निर्वाचन।
Politics, Women, Chhattisgarh, Election.

प्रस्तावना

शोध पत्र जिसका विषय राजनीतिक दल और महिलाएँ छत्तीसगढ़ के संसदीय औरविधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में (1950-2000) महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी है। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सफलता का एक प्रमुख कारण उन्हें प्राप्त राजनीतिक दलों का समर्थन है, यद्यपि छत्तीसगढ़ में दलों की स्थिति में परिवर्तन होता रहा है तथापि प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रस दल की प्रधानता रही है। महिलाओं को सबसे अधिक कांग्रेस दल से समर्थनप्राप्त हुआ है। कांग्रेस समर्थित महिलाआंे ने संसद और विधानसभा में अन्य दलों की अपेक्षा ज्यादा प्रतिनिधित्व किया है। यद्यपि स्थानीय निर्वाचन में अन्य दल की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। कांग्रेस के अलावा जनसंघ, भाजपा, राम राज्य परिषद, कम्यूनिस्ट पार्टी आदि दलों ने भी महिलाओं को अपना पूरा सर्मथन दिया।

अध्ययन का उद्देश्य

शोध पत्र का उद्देश्य संसदीय चुनाव और विधानमण्डल चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है इसका अध्ययन किया जाना है। अन्य

क्षेत्रों की तरह राजनीति में भी महिलाओं ने आजादी के बाद अपनी विभिन्न भूमिका का निर्वाहन किया है पर इसमें उनकी भागीदारी के "आंकड़ों का यदि विश्लेषण किया जाये तो उनमें राजनीतिक दलों का महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में कितना योगदान रहा है यही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।'

शोध विधि

शोधपत्र के लिये तथ्यों को विभिन्न पहलुओं में एकत्रित कर सैम्पलिंग अवलोकन तथ्य विश्लेषण आदि विधियों का प्रयोग किया गया। इसमें मूलतः प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

छत्तीसगढ़ में राजनैतिक दलों का इतिहास

1985 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी इसके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की लहर उठने लगी थी। माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, ई. राघवेन्द्र राव. पं. सुन्दरलाल शर्मा आदि इसके प्रमुख नेता थे। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास किया।

1919 के अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार व प्रांतीय असेम्बली के लिये चुनाव का प्रावधान किया गया। कांग्रेस के अंदर ही एक नयी स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता ई. राघवेन्द्र राव 1923 में कांग्रेस से अलग हो गये व 1926 में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। यद्यपि वे चुनाव जीत गये पर उनकी पार्टी के अन्य सारे प्रत्याशी हार गये थे।

1920 ई. में महात्मा गाँधी द्वारा कांग्रेस के मंच से चलाये गये असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सन् 1937 के अधिनियम के द्वारा देश में लोक प्रिय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था इनमें विजयी सभी प्रत्याशी कांग्रेस के थे क्योंकि किसी दूसरे राजनीतिक दल का असतित्व नहीं था।1

आजादी के बाद आम चुनाव में राजनीतिक दल (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

1947 में भारत की आजादी के बाद 1952 में लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव हुये। 1951 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, रामराज्य परिषद्, किसान मजदूर पार्टी का उदय हुआ और इनके प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुये।

1952 के चुनाव में जहाँ समाजवादी पार्टी व किसान मजदूर पार्टी ने भाग लिया वहीं प्रजा समाजवादी पार्टी में किसान मजदूर पार्टी का विलय हो गया। 1957 में हुये आम चुनाव में समाजवादी पार्टी का छत्तीसगढ़ से लोप हो गया। 1977 के चुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी एवं रामराज्य परिषद् को सफलता मिली पर कांग्रेस का ही वचर्वस्व रहा। 1962 में पहली बार जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुये, प्रजा समाजवादी पार्टी की सीटें बट गई। 146 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। रामराज्य परिषद् की सीट पूर्ववत रहीं। 13 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते। 1967 और 1972 के लोकसभा-विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1977 में सर्वप्रथम जनता पार्टी का शासन कायम हुआ। जनता पार्टी में दो ही घटक शामिल थंे, जनसंघ व समाजवादी। इसके अतिरिक्त कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी भी 1957 के चुनाव से खड़े हो रहे थे परंतु 1967 तक एक भी प्रत्याशी सफल नहीं हो पाये। 1980 में पहली बार दन्तेवाड़ा विधानसभा से कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुये। 1980 में जनता सरकार के पतन के पश्चात् जनसंघ ने अपने स्वरूप को भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित कर दिया और समाजवादी पार्टी जनता पार्टी में विलीन हो गई। 1980 और 1985 के चुनाव में भाजपा को कोई विशेष सफलता नहीं मिली कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। यद्यपि 1990 के चुनाव में 90 सीटों में से 51 सीटों पर भाजपा को सफलता मिली जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर ही सीमित रह गई। 1993 में विधानसभा के चुनाव में फिर कांग्रेस को सफलता मिली। 1998 के केन्द्र में भाजपा सरकार बनी पर राज्य में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1 नवम्बर 2000 को बने गये छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा का बहुमत रहा।2

राजनीतिक दल और महिलाएँ

महिला और पुरूषों के बीच इतना अधिक अंतर कहीं नहीं है, जितना राजनैतिक भागीदारी में है। चार दशकों से अधिक समय से हमारे देश में राजनीतिक दल महिलाओं को चुनाव लड़ने में समान अवसरों से वंचित करते रहे हैं। अतः इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आठवीं लोकसभा में महिलाओं को 44 सदस्यों के साथ केवल 8.18 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला किन्तु हैरानी की बात यह है कि दसवीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होकर 7 प्रतिशत रह गया है। राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में भी यही स्थिति है।3

आजादी के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें महिलाओं को समान राजनैतिक व सामाजिक अधिकार देने की बात कहीं गयी थी। आँकड़े बताते है कि आजादी के बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और निर्णयात्मक पदों पर उनकी उपस्थिति अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही है। महिलाओं की राजनीतिक निष्क्रियता और सत्ता में उनकी भागीदारी की कमी के कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व पारिवारिक कारण रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिये अन्य कारणों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों का महिलाओं के प्रति नजरिया भी एक प्रमुख कारण है।

संसदीय चुनाव में दलीय स्थिति

पुराने मध्यप्रदेश जिसे सी.पी. एण्ड बरार कहा जाता था में 15 रियासतें थी जिनमें 13 हजार वर्गमील की बस्तर रियासत सबसे बड़ी थी और 138 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली शक्ति रियासत सबसे छोटी। 23 दिसम्बर 1947 को केन्द्र सरकार की एक सूचना के प्रकाशन के साथ पुराने मध्यप्रदेश की रियासतों का विलीनीकरण कर दिया गया। स्वाधीनता के पश्चात् 1952 को पहला आम चुनाव हुआ।

राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवम्बर 1956 को पुराने मध्यप्रदेश की चार इकाईयाँ - विंध्यप्रदेश, महाकौशल, मध्यभारत और भोपाल को मिलाकर नवीन मध्यप्रदेश का निर्माण किया गया। नवीन मध्यप्रदेश का प्रथम चुनाव 1957 को हुआ। 1 नवम्बर 2000 को नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। 1 नवम्बर 2000 से पूर्व यह मध्यप्रदेश राज्य का ही दक्षिण-पूर्वी हिस्सा था।

मध्यप्रदेश में 40 लोकसभा क्षेत्र थे जिसमें 11 छत्तीसगढ़ क्षेत्र से थे। जो इस प्रकार था - सरगुजा, रायगढ़ जांजगीर, बिलासपुर, सारंगढ़, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर दुर्ग व राजनांदगाँव।

मध्यप्रदेश राज्य के लाकेसभा चुनाव में दलीय स्थिति (छत्तीसगढ़ के गठन पूर्व)

निम्नांकित तालिका से मध्यप्रदेश में 1952 से 1996 तक विभिन्न राजनीतिक दलों की दलीय स्थिति स्पष्ट होती है। 1 नवम्बर 2000 से पूर्व छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राज्य का ही हिस्सा

था। अतः इससे छत्तीसगढ़ की दलीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।5

तालिका 1 वर्ष 1957 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति।

वर्ष 1957	
कुल सीट	38
कांग्रेस	35
हिन्दू महासभा	1
रिक्त	2

तालिका 2 वर्ष 1962 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1962	
कुल सीट	38
क्रांग्रेस	24
जनसंघ	3
समाजवादी	1
प्रजा समाजवादी	3
क्रांतिकारी	4
निर्दलीय	2
आर.पी.आर	1

तालिका 3 वर्ष 1967 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1967	
कुल सीट	37
क्रांग्रेस	25
जनसंघ	10
प्रजा समाजावादी	1
निर्दलीय	1

तालिका 4 वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1971	
कुल सीट	37
क्रांग्रेस	21
जनसंघ	11
संयुक्त मोर्चा पार्टी	1
निर्दलीय	4

तालिका 5 वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1977	
कुल सीट	40
क्रांग्रेस ई.	1
भारतीय लोकदल	37
रिपब्लिकन लोकदल	1
निर्दलीय	1

तालिका 6 वर्ष 1980 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1980	
कुल सीट	40
क्रांग्रेस	35
जनता	4
निर्दलीय	1

तालिका 7 वर्ष 1984 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1984	
कुल सीट	40
क्रांग्रेस	40

तालिका 8 वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1989	
कुल सीट	40
क्रांग्रेस ई.	8
भाजपा	27
जनता दल	5

तालिका 9 वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1991	
कुल सीट	40
क्रांग्रेस ई.	27
भाजपा	12
बसपा	1

तालिका 10 वर्ष 1996 में लोकसभा चुनाव में दलीय स्थिति

वर्ष 1996	
कुल सीट	40
क्रांग्रेस ई.	8
भाजपा	27
क्रांग्रेस	2
विकास कांग्रेस	1
निर्दलीय	2

छत्तीसगढ़ में महिलाओं की राजनीति का केन्द्र बिन्दु यदि कांग्रेस को कहा जाये तो गलत नहीं होगा क्योंकि सर्वाधिक उम्मीद्वार कांग्रेस दल ने ही खड़े और विजयी महिला उम्मीद्वार भी कांग्रेस दल के ही सबसे अधिक रहे। सारणी से स्पष्ट है कि 1957 से 1998 में हुये लोकसभा चुनाव में कुल 7 महिलाएँ 14 बार संसद पहुँची, जो कि संतोषप्रद नहीं कह सकते। अन्य दलों में मात्र भाजपा की एक मात्र सांसद श्रीमति करूणा शुक्ला हैं जो वर्ष 2003-04 के लोकसभा चुनाव में जांजगीर क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखंे तो कांग्रेस की 7 महिला प्रत्याशी विजयी रही और भाजपा की 1 महिला उम्मीद्वार सफल हुई। राजनैतिक दलों में महिलाओं की स्थिति को हम नीचे दिये गये तालिका से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 1952 से 1998 के बीच हुये विधानसभा चुनावों में राजनैतिक दलों ने कितनी महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा और कितनी महिलाएँ विजयी रही इस विवरण इस प्रकार हैं4:-

सारणी

छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीद्वारों की संख्या एवं स्थिति

(1952-98)

	कांग्रेस	जनसंघ	निर्दलीय	जनता पार्टी	आर. आर. पी.	पी. एस. पी.	एस. ओ. सी.	महायोग
1952	**कुल प्रत्याशी**	3 3	- -	- -	1 -	- -	- -	4 3
1957	**जीते**	7 7	1 0	- -	1 0	- -	- -	9 7
1962	**कुल प्रत्याशी**	7 4	1 0	3 0	1 1	1 0	- -	13 5
1967	**जीते**	1 1	1 0	1 1	- -	- -		3 2
1972	**कुल प्रत्याशी**	3 2	- -	3 1	- -	- -	1 0	7 3
1977	**जीते**	2 1	- -	4 1	- -	- -		6 2

सारिणी

छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीद्वारों की संख्या एवं स्थिति

		कांग्रेस	भाजपा	सी.पी.आई.	निर्दलीय	बसपा	गोंगपा	आरपीआई	जनता दल	छसपा	शिव सेना	समता पार्टी	लोक दल	अजेय भारत पार्टी	एस.ओ. सी.	दूरद र्शी	शोषित समाज पार्टी	योग
1980	कुल प्रत्याशी	6 6	3 0	- -	1 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 6
1985	जीते	11 8	1 1	1 0	13 1	- -	- -	- -	1 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	27 10
1990	कुल प्रत्याशी	9 2	1 0	1 0	17 0	1 0	- -	- -	1 0	- -	- -	- -	1 0	- -	- -	1 0	- -	32 2
1993	जीते	5 2	2 1	- -	22 0	8 0	2 0	1 0	2 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 0	- -	46 3
1998	कुल प्रत्याशी	7 4	8 2	2 0	17 0	8 0	7 0	2 0	2 0	3 0	2 0	2 0	1 0	1 0	- -	- -	2 0	64 6

(1980-98)

शोधकर्ता अभिमत से उपरोक्त तालिका के आधार पर अब तक के चुनावों के नतीजों को देखा जाये तो महिला प्रत्याशियों के चयन के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा हैं उसने 6.1 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें 40 बार महिला

प्रत्याशी जीत कर विधानसभा में पहुँची भाजपा (जनसंघ, भाजपा, जनता 77) ने अब तक 20 महिलाओं को टिकट घर खड़ा किया। जिसमें 6 महिलाएँ विजय हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप खड़ी हुई, 81 में से 4 महिलाओं को विजयी मिली।

अन्य दलों में आर. आर. पी. (राम राज्य परिषद) की दो महिलाएँ 1957 और 1962 के चुनावी समर में खड़ी हुई, जिसमें 1962 में एक महिला उम्मीद्वार को सफलता मिली। पी.एस.पी. (प्रजा सोसलिस्ट पार्टी) की एक महिला प्रत्याशी 1962 कें चुनाव में उम्मीद्वार थी पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1972 में एस. ओ. पी. ने एक महिला उम्मीद्वार को चुनाव में टिकट दी पर वे असफल हो गई। सी.पी. दल की चार महिलायें वर्ष 1985 और 1990, 1998 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी पर कोई सफल नहीं हो पाई।

महिलाओं को टिकट देने के मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दल भी पीछे रहे, बसपा ने कुल 17 सीटों में महिलाओं को टिकट दी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों से महिलाओं को टिकट दी पर एक भी सफल नहीं हो सकी।

जनता दल ने 1988 से 1998 के बीच 6 महिलाओं को चुनावी समर में खड़ा किया पर इनकी भी कोई प्रत्याशी विजयी नहीं हुई। आर. पी. आई. दल ने 3 महिला उम्मीद्वारों को सन् 1993 व 1998 के चुनाव में टिकट दी पर इनकी भी कोई महिला विधायक नहीं बन पायी।

छसपा (छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी) ने 3 महिला उम्मीद्वारों को टिकट दी। सन् 1998 के विधानसभा चुनाव में तीनो प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना दल ने 1998 में दो महिलाओं को टिकट दी पर दोनों ही महिला चुनाव हार गई। समता पार्टी ने 1998 के चुनाव में दो महिला उम्मीद्वार खड़े किये पर सफलता नहीं मिल पायी। लोकदल ने 1990 और 1998 में दो महिला प्रत्याशी खड़े किये पर वे हार गयीं। अजेय भारत पार्टी ने 1998 में 1 महिला उम्मीद्वार को अपना प्रत्याशी बनाया पर सफलता नहीं मिली। दूरदर्शी पार्टी से 1990 व 1997 में न्यूनतम दो महिला उम्मीद्वार ही विजयी रहीं।

समाजवादी पार्टी ने 1998 में दो महिलाओं को राजनीति में उतारा पर दोनो असफल हो गईं। 1952 से 1998 के बीच हुये विधानसभा चुनावों में 1998 में सर्वाधिक 64 एवं सबसे कम 1967 में मात्र 3 महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ी। सन् 1985 के चुनाव में सर्वाधिक 10 महिला प्रत्याशी एवं वर्ष 1990 एवं 1967 न्यूनतम दो महिला उम्मीद्वार ही विजयी रहीं।

1952 से लेकर 1998 तक के विधानसभा चुनावों तक राजनैतिक दलों में कांग्रेस ने महिलाओं को ज्यादा अवसर दिया। आजादी के तुरंत बाद राम राज्य परिषद ने और जनसंघ ने महिलाओं को एक-दो अवसर अवश्य दिये लेकिन बाद में भाजपा ने भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अन्य दलों ने भी महिलाओं को राजनीति में सक्रिय किया।

आजादी के बाद सामान्यतः राज परिवार से संबंधित या शिक्षित वर्ग से संबंधित महिलाएँ ही राजनीति में सक्रिय थी। लेकिन शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बाद सामान्य महिलाएँ भी राजनीति में सक्रिय हुई, महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को लेकर समय-समय पर हर वर्ग में विचार-विर्मश होता रहा और इसी का परिणाम है कि अब औपचारिक तौर पर सभी राजनैतिक दल महिलाओं को एक निश्चित संख्यात्मक आरक्षण देने के लिये तत्पर हैं।

विधान सभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की कुल 90 में से 57 सीटें ऐसी हैं जहाँ से आज तक किसी भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया जबकि 33 सीटों पर प्रमुख दलों ने कई महिलाओं का निरंतर अवसर दिया है।6

निष्कर्ष

विभिन्न दलों के संगठनात्मक ढाँचे में महिलाओं की भागीदारी का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले एक शोध परक दृष्टि से कांग्रेस ने अपने संगठन में लगभग 10 प्रतिशत स्थान/पद महिलाओं को उपलब्ध कराया है। अन्य दलों के मुकाबले में यह प्रतिशत जरूर अधिक है लेकिन पुरूषों की तुलना में बहुत असंतोषजनक माना जाएगा। पार्टी संगठन में महिलाओं की भागीदारी का यह प्रतिशत भाजपा में 6 प्रतिशत, तीसरे मोर्चे के दलों में 7 प्रतिशत, मार्क्सवादी पार्टी में 6 प्रतिशत आर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी में 8 प्रतिशत के आसपास हैं।

शोधकर्ता से विभिन्न राजनीतिक दल के घोषणापत्र के आधार पर तो महिलाओं के वे हितैषी लगते हैं और सभी चाहते हैं कि महिलाएँ राजनीतिक रूप से जागरूक हों, क्रियाशील बने और सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। अधिकतर दलों के संविधान तथा घोषणा पत्रों मे तो महिलाओं का खूब जिक्र है लेकिन उनके संगठनों में महिलाओं की कमी है।

महिलाओं को राजनीति में कम दिलचस्पी होने के कई कारण है राजनीतिक कार्यो के लिये कोई निश्चित समय सीमा नही है।जैसे जबकि अन्य क्षेत्रों जैसे बैंक, शिक्षा आदि में निश्चित समय सीमा होने के कारण महिलाओं ने इन क्षेत्रों में ज्यादा रूची रखी महिलाओं को अपने संसदीय और विधानसभा निर्वाचनों में लंबे दौरे करने पड़ते है और साथ ही परिवार में भी समन्वयन स्थापित करना पड़ता है इससे भी महिलाएं राजनीति की ओर स्वाधीनता के बाद उतनी अग्रसर नही हुयी जितना कि अन्य क्षेत्रों में संख्या दिखाई पड़ती है। आवश्यकता इस बात कि है कि महिलाओं को परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिले और वे परिवार के साथ राजनीति में पर्दार्पण करके सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर सके। साथ ही महिलाओं का शिक्षित होना भी आवश्यक है ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावकारी ढंग से संसद और विधानसभा में प्रश्नों के रूप रख सके। और महिलाओं को स्वयं भी अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र भी अन्य अन्य क्षेत्रों की भांति है और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति पूर्ण कराकर वे देश हित, समाज हित में कार्य कर सकती है।इन सबके लिये राजनैतिक दलों की भूमिका प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है जिसमें विभिन्न दल महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचन में उतारें और उन्हे मंत्री मंडल में भी प्रमुख स्थान दे।

महिलाओं की राजनैतिक क्षेत्र में सफलता का एक प्रमुख कारण उन्हें प्राप्त राजनीतिक दलों का समर्थन है, यद्यपि छत्तीसगढ़ में दलों की स्थिति में परिवर्तन होता रहा है प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दल की प्रधानता रही है। महिलाओं को सबसे अधिक कांग्रेस दल से सर्मथन प्राप्त हुआ। कांग्रेस समर्पित महिलाओं ने संसद और विधानसभा में अन्य दलों की अपेक्षा ज्यादा प्रतिनिधित्व किया है। यद्यपि स्थानीय निर्वाचन में अन्य दलों की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। कांग्रेस के अलावा जनसंघ, भाजपा, राम राज्य परिषद, कम्यूनिस्ट पार्टी आदि दलों ने भी महिलाओं को अपना पूरा समर्थन दिया।

यद्यपि महिलाएँ तेजी से राजनीति के क्षेत्र में आ रही हैं, तथापि उन्हें राजनीति में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक सोच का अभाव आदि ऐसी प्रमुख बाधाएँ हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती हैं।

महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिये उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वालम्बी बनाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास को दूर कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का दायित्व है। भ्रष्ट्राचार और शोषण से महिलाओं को मुक्त करके उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता हैं।महिलाओं में राजनीतिक जागरण की आवश्यकता है। राजनीति जागरण से मेरा तात्पर्य उनका शिक्षित और संस्कारित होना आवश्यक है अतः भारतीय परिवार में नारी का सर्वप्रथम दायित्व पत्नीत्व और मातृत्व के साथ राजनैतिक कार्यकलाप का समन्वय होना अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *हरिशचंद्र शर्मा, भारत में राज्यों की राजनीति पृष्ठ 258-259 वर्ष 2002*
2. *गिरिजाशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ की राजनीति व आमचुनाव पृष्ठ 6-8, वर्ष 2003*
3. *वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग 1992-93 पृष्ठ 45*
4. *लोकसभा सचिवालय एवं विधानसभा सचिवालय कार्यवाहियों के विभिन्न वर्षों के विभिद अंक*
5. *सदस्य संदर्भ विधानसभा सचिवालय रायपुर द्वारा प्रकाशित (पृष्ठ 242 से 247) वर्ष 2003*
6. *Based on election commision report 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1985, 1990, 1993, 1998*